



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 30 सितम्बर, 2024

आश्विन 8, 1946 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त विभाग

संख्या बी-4-590/दस-2024-10(4)-2006

लखनऊ, 30 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार की संहत निक्षेप निधि के गठन एवं प्रशासन के लिए संशोधित योजना

अधिसूचना संख्या-52/X-2020-10(4)-2006, दिनांक 17 मार्च, 2020 को अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश सरकार संहत निक्षेप निधि को स्थापित करने के लिए संशोधित योजना को निम्नवत अधिसूचित करती है :-

योजना का शीर्षक

1-यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे "सरकार" कहा गया है) की "संहत निक्षेप निधि (जिसे आगे 'निधि' कहा गया है) योजना" कही जायेगी।

निधि का गठन

2-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने अदत्त दायित्व के मोचन के लिए निधि का गठन किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

3-इस निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारम्भ करते हुए सरकार के अदत्त दायित्वों के मोचन हेतु ऋण शोधन निधि की तरह किया जायेगा।

योजना के संचालन का प्रारम्भ

4-यह निधि अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगी। योजना का संचालन निम्नानुसार है :

स्पष्टीकरण:-

(क) यह निधि सरकार द्वारा अंगीकृत वर्तमान संहत निक्षेप निधि योजना के अधीन उल्लिखित विद्यमान निधि को प्रतिस्थापित करेगी।

(ख) मार्च, 2024 की समाप्ति पर वर्तमान संहत निक्षेप निधि योजना के अधीन विद्यमान निधि की अवशेष धनराशियाँ इस निधि को स्थानान्तरित कर दी जायेंगी।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान संहत निक्षेप निधि से निकासी हेतु अधिकतम अर्ह/पात्र सीमा पर पहुंचने के लिए, संहत निक्षेप निधि में, उसके पूर्ववर्ती द्वितीय वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को अवशेष कोष का 50 प्रतिशत अथवा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान देय होने वाले मोचन की धनराशि, दोनों में से जो कम हो, की गणना की जानी चाहिए।

(घ) इस निधि का उपयोग सरकार के अदत्त दायित्वों के मोचन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(च) राज्य सरकार अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए संहत निक्षेप निधि में किए गए निवेश के आनुषंगिक के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के अधीन अल्पकालिक सुविधा का लाभ उठा सकती है, जो कि बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शर्तों और उपबन्धों के अधीन होगा।

(छ) अदत्त दायित्वों को सरकार का आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा दायित्वों दोनों को सम्मिलित करने हेतु परिभाषित किया गया है।

निधि में अंशदान

5-सरकार पांच वर्ष की अवधि के भीतर अदत्त दायित्वों के पांच प्रतिशत तक संहत निक्षेप निधि कोष का निर्माण करने की दिशा में सचेष्ट प्रयास करेगी। एक वर्ष में अंशदान करने की संख्या के संदर्भ में निधि में ऐसे अंशदानों की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। सरकार स्व-विवेकानुसार किसी भी समय सामान्य राजस्व से या विनिवेश आय जैसे अन्य स्रोतों से निधि में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार रिजर्व बैंक से उधार लेकर निधि में अपना अंशदान नहीं करेगी।

निधि का सामान्य राजस्व के साथ संबंध

6-निधि कोष में नियत कालिक अंशदान के साथ-साथ निधि से अर्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से पृथक रखा जायेगा। निधि का उपयोग इस योजना में विहित रीति से किया जाएगा।

निधि का प्रशासन

7-निधि का प्रबन्धन बैंक के नागपुर स्थित केंद्रीय लेखा अनुभाग द्वारा (ऐसे निर्देशों/अनुदेशों के अध्वधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाये) किया जायेगा।

निधि के कोष का निवेश

8-निधि में अभिवृद्धि होने वाली राशियों का निवेश ऐसी परिपक्वता अवधि वाली भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, राजकोषीय बिलों, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों तथा अन्य राज्यों के राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जायेगा, जैसा सरकार के परामर्श से बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

स्पष्टीकरण:-

(क) निधि में अभिवृद्धि होने वाली राशियों में, किये जाने वाले आवर्तक अंशदान तथा उसके निवेश से निधि में संचित होने वाली आय सम्मिलित होगी।

(ख) बैंक द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों अर्जित करके निवेश के लिए प्रस्तर-10 में इंगित प्रभार से भिन्न कोई अन्य प्रभार लगाये बिना प्रतिभूतियों उपलब्ध करायेगा।

लेखा संव्यवहार

9-(क) बैंक सरकार की सलाह के अनुसार अपने पास रखे गये सरकार के नामे खाते बढ़ाने की व्यवस्था करेगा।

(ख) निधि में किये जाने वाले अंशदान का निवेश, ₹0 10,000/- के गुणकों में, जैसा प्रस्तर-8 में इंगित किया गया है बैंक द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों में किया जायेगा।

(ग) ब्याज आय के माध्यम से निधि में नियत कालिक अभिवृद्धि को बैंक द्वारा वैसी ही रीति से, ₹0 10,000/- के गुणकों में, पुनर्निवेशित किया जायेगा।

(घ) निधि से किये गये और योजना के प्रचलन के दौरान परिपक्व होने वाले निवेश को प्रस्तर-8 के अनुसार पुनर्निवेशित किया जायेगा।

(च) निधि से कोई निकासी की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि निधि के गठन की तिथि से पाँच वर्ष पूरे न हो जाय।

स्पष्टीकरण:—

(क) निधि के गठन की तिथि से पाँच वर्ष पूरे होने पर अगले वित्तीय वर्ष से निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) आवर्ती किश्तों हेतु सरकार के नामे डाली गयी धनराशि का लेखांकन मुख्य लेखाशीर्ष-8222 (रक्षित निधियों) के अन्तर्गत किया जायेगा। ऋण की परिपक्वता पर लेखाशीर्ष-8222 (उपशीर्ष निक्षेप निधि) में अवशेष राशि लेखाशीर्ष-8680 (विविध सरकारी लेखा) खाता से शेष समायोजन लेखा में जमा की जायेगी।

(ग) बैंक सामान्य प्रक्रिया में निवेश की राशि में से प्रासंगिक शुल्कों की धनराशि घटाते हुए सरकार को सूची प्रेषित करेगा। यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश संव्यवहारों को अन्य संव्यवहारों के साथ मिश्रित न हो, इन्हें अलग-अलग सूची में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।

(घ) बैंक निर्धारित तिथियों पर निवेश पर ब्याज का संग्रहण तथा उसे निधि में क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित करेगा।

(च) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर बैंक प्रतिभूतियों के मोचन का प्रबन्ध करेगा। किसी दावे के भुगतान के दायित्व की पूर्ति हेतु परिपक्वता से पूर्व विनिवेश के मामले में, बैंक नगदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा तथा उन प्रतिभूतियों को तत्समय प्रभावी मूल्य पर विक्रय कर प्राप्त धनराशि में से प्रासंगिक शुल्कों को घटाकर निधि में क्रेडिट किया जायेगा। यदि ये प्रतिभूतियों घाटे में हैं, बैंक सरकार के परामर्श से नगदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा। डेबिट स्कॉल्स के मामले में प्राप्तियों के लिए बैंक अलग-अलग स्कॉल्स का प्रयोग करेगा।

(छ) आवर्ती अंशदान के कारण व्यय के लिए सरकार के बजट में सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत प्रावधान कराया जायेगा। निधि से वित्त पोषित होने वाले व्यय की सीमा तक धनराशि का प्रत्याहरण, निधि से किये गये निवेश के निपटान द्वारा किया जायेगा।

(ज) बैंक निधि के नाम से एक चालू खाता तथा सब्सिडियरी जनरल लेजर खाता खोलेगा एवं प्रत्येक वर्ष सितम्बर तथा मार्च की समाप्ति पर निवेशों का विवरण प्रदर्शित करते हुए सरकार को विवरणी उपलब्ध करायेगा।

निधि के प्रशासन हेतु सेवा शुल्क	10—सरकार बैंक को निधि के आवर्तन पर एक प्रतिशत का 1/8 प्रतिशत अथवा समय-समय पर परस्पर निर्णय की जाने वाली दर पर कमीशन का भुगतान करेगी।
लेखा और संपरीक्षा	11—निधि तथा किये गये निवेशों का लेखा सामान्य क्रम में राज्य के महालेखाकार द्वारा रखा जायेगा। बैंक सहायक खातों को ऐसे रीति और विवरण में अनुरक्षित करेगा जैसा कि सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विचार किया जा सकता है।
व्यावृत्ति	12—योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु सरकार समय-समय पर योजना के उपबन्धों से सम्बन्धित निदेश जैसा अवधारित किया जाय, जारी करेगी। योजना के किसी उपबन्धों के संचालन में कोई कठिनाई होने के मामले में सरकार, यदि समाधान हो जाय तो ऐसे उपबन्धों को शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. B-4-590-X-2024-10(4)-2006, dated September 30, 2024 :

No. B-4-590-X-2024-10(4)-2006

Dated Lucknow, September 30, 2024

REVISED SCHEME FOR CONSTITUTION AND ADMINISTRATION OF
THE CONSOLIDATED SINKING FUND
OF

THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

IN suppression of the Notification No. 52/X-2020-10(4)/2006 Dated March 17, 2020, the Government of Uttar Pradesh, hereby, notifies the revised scheme for setting up of the Consolidated Sinking Fund of Government of Uttar Pradesh follows;

Title of the Scheme	1. The Scheme shall be called 'Consolidated Sinking Fund (hereinafter referred to as 'the Fund') Scheme' of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as 'the Government').
Constitution of the Fund	2. The Fund will be constituted by the Government of Uttar Pradesh for redeeming its outstanding liabilities.
Objective of the Scheme	3. The Fund is to be utilised as an Amortisation Fund for redemption of the outstanding liabilities of the Government commencing from the financial year 2024-25.
Commencement of the Operation of the Scheme	4. The Fund shall come into force with effect from the date of the notification. The Operation of the Scheme is as under.

Explanation:-

(a) The Fund shall substitute the existing fund mentioned under the extant CSF scheme adopted by the Government.

(b) The outstanding balances of the existing fund under the extant CSF Scheme as at end-March, 2024 shall be transferred to the Fund.

(c) 50 per cent of the outstanding corpus held in the CSF as on March 31 of the second preceding financial year, or the amount of redemption falling due during the financial year (April-March), whichever is less, should be reckoned for arriving at the maximum eligible limit for withdrawal from the CSF during the year.

	<p>(d) The Fund shall not be utilised for any purpose other than redemption of the outstanding liabilities of the Government.</p> <p>(e) The State Government can avail of short-term accommodation under Special Drawing Facility (SDF) from Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') against the collateral of investment made in CSF for meeting temporary cashflow mismatches, subject to the terms and conditions as fixed by the Bank from time to time.</p> <p>(f) The outstanding liabilities is defined to comprise both internal debt and public account liabilities of the Government.</p>
Contributions to the Fund	<p>5. The Government should make conscious efforts towards building up the CSF corpus to five per cent of the outstanding liabilities within a span of five years. There is no ceiling on such contributions to the Fund in terms of number of times of making contributions in a year. It is open to the Government to invest in the Fund from the General Revenue at any time or from other sources such as disinvestment proceeds, at its discretion. The Government shall not fund its contribution to the Fund out of borrowings from the Reserve Bank.</p>
Relationship of the Fund with General Revenues	<p>6. The corpus of the Fund comprising the periodic contributions as well as the income accruing to the Fund shall be kept outside the General Revenue of the Government. The Fund shall be utilized in the manner prescribed in this Scheme.</p>
Administration of the Fund	<p>7. The Fund shall be administered by Central Accounts Section of the Bank at Nagpur, (subject to such directions / instructions as the Government may issue from time to time).</p>
Investment of the corpus of the Fund	<p>8. The accretions to the Fund shall be invested in Government of India (GoI) dated Securities, Special Securities of GoI, Treasury Bills and State Government securities of other States of such maturities as the Bank may determine from time to time in consultation with the Government.</p>
	<p>Explanation:-</p> <p>(a) The accretions to the Fund shall include the periodic contributions and the income accruing to the Fund from investment thereof.</p> <p>(b) The Bank will make available the securities for investment by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 10.</p>
Account Transactions	<p>9. (a) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the advice of the Government.</p> <p>(b) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank in Government Securities as indicated in paragraph 8 in multiples of Rs.10,000/-.</p> <p>(c) The periodic accretion to the Fund by way of interest income shall be reinvested by the Bank in a similar manner, in multiples of Rs.10,000/-</p> <p>(d) The investments held in the Fund and maturing during currency of the scheme shall be reinvested in accordance with paragraph 8.</p> <p>(e) No withdrawals will be allowed from the Fund until completion of five years from the date of constitution of the fund.</p> <p>Explanation:-</p> <p>(a) Withdrawals may be allowed starting from the next financial year on completion of five years from the date of constitution of the fund.</p> <p>(b) The debit to Government on account of the periodic installments will be accounted under the major head 8222 (Reserve Funds). On the maturity of the loan, the balance outstanding under the head 8222 (sub-head Sinking Fund) will be credited to the head 8680 (Miscellaneous Government Account) Ledger Balance Adjustment Account.</p> <p>(c) The Bank shall scroll to the Government the debit on account of investment less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these will be indicated distinctly in separate scrolls.</p> <p>(d) The Bank shall arrange to collect interest on the investments and credit the same to the Fund on the due dates.</p>

(e) On the maturity of the securities, the Bank shall arrange to redeem the securities. In case of premature disinvestment to meet the liability on account of the claims to be paid, the Bank will decide on the securities to be liquidated and sell the securities at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges, to the Fund. If these securities are in loss, Bank may in consultation with the Government decide on the securities to be liquidated. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(f) The provision for expenditure on account of the periodic contributions shall be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal of the investment.

(g) The Bank shall open a Current Account and Subsidiary General Ledger Account in the name of the Fund and furnish to the Government as at the end of September and March each year, a statement showing the details of investments.

Service charges for
administration of the
Fund
Accounts and Audit

10. The Government shall pay to the Bank a commission at the rate of 1/8 per cent of one per cent on the turnover of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time.

11. The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The Bank will maintain subsidiary accounts in such manner and details as may be considered by the Government in consultation with the Accountant General.

Savings

12. The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.